

TRAI RECOMMENDATIONS ON "CLOUD SERVICES"

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has released Recommendations on "Cloud Services", after a multistage consultation process.

Earlier, TRAI has sent its recommendations on Cloud services to the Government of India on 16th August 2017. It included the Legal and Regulatory framework for Cloud Services, Interoperability, Legal framework for CSPs operating in multiple jurisdictions etc. The Government has accepted all the recommendations and sought additional recommendations on the framework for CSPs' i.e. "the terms and conditions of registration of Industry body, Eligibility, entry fee, the period of registration, and governance structure, etc." vide DoT's letters dated 27th September 2018 and 6th May, 2019.

In arriving at these recommendations on 'Cloud Services', TRAI issued a consultation paper on 23rd October 2019 inviting inputs on the number of industry bodies, requirements for any CSP to become a member of an industry body, membership fee, governance structure and initial seeding of industry body, etc. for comments and counter comments from stakeholders. Subsequently, an Open House Discussion (OHD) was held on 28th February 2020 at Delhi, where stakeholders participated and deliberated on the issues.

The salient features of the recommendations are:

- i. Initiating a light touch regulatory framework by setting up an industry body through a three-step process: enrollment of CSPs operating in India; formation of an ad hoc body to frame broad rules, organizational structure, election procedure, etc.; and the election of



ट्राई की 'क्लाउड सेवाओं' पर सिफारिशें

भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने विभिन्न चरणों वाली परामर्श प्रक्रियाओं के बाद 'क्लाउड सेवाओं' पर सिफारिश जारी की है।

इससे पहले ट्राई ने क्लाउड सर्विस पर अपनी सिफारिशों को 16 अगस्त 2017 को भारत सरकार को भेजा था। इसमें क्लाउड सेवाओं के लिए वैधानिक व नियामक ढांचा और विभिन्न क्षेत्राधिकार में सीएसपी के संचालन के लिए वैधानिक ढांचा, इंटरऑपरेबिलिटी आदि शामिल था। सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और सीएसपी यानि उद्योग निकाय के पंजीकरण शर्तों, पात्रता, प्रवेश शुल्क, पंजीकरण की अवधि व शासन संरचना आदि की रूपरेखा पर अतिरिक्त सिफारिशों की मांग की है। यह मांग डॉट के 27 सितंबर 2018 व 6 मई 2019 के पत्रों से गयी।

क्लाउड सेवाओं पर इन सिफारिशों पर पहुंचने के लिए ट्राई ने 23 अक्टूबर 2019 को एक परामर्श पत्र जारी किया था जिसमें उद्योग निकायों की संख्या, किसी भी सीपीसी के लिए एक उद्योग निकाय के सदस्य बनने के लिए आवश्यकतायें, सब्सक्रिप्शन शुल्क, शासन संरचना और आरंभिक सीडिंग हितधारकों की ओर से टिप्पणियां व जवाबी टिप्पणियां आमंत्रित की गयी। इसके बाद 28 फरवरी 2020 को दिल्ली में एक ओपन हाउस विचार-विमर्श (ओएचडी) आयोजित किया गया, जहां हितधारकों ने भाग लिया और मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

सिफारिश की मुख्य विशेषतायें हैं:

- i. तीन चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से उद्योग निकाय स्थापित करने के लिए एक हल्का फुल्का नियामक ढांचा स्थापित करना, भारत में काम करने वाले सीएसपी का नामांकन, व्यापक नियमों, संगठनत्मक संरचना, चुनाव प्रक्रियाओं आदि की रूपरेखा के लिए एक तदर्थ निकाय का गठन और एक नियमित उद्योग के नेतृत्व वाली निकाय

office bearers to take over its functioning as a regular industry-led body.

- ii. Industry body to be registered under the Societies Registration Act, 1860, and to be formed using the approach followed for the formation of the M2M body by DoT.
- iii. Scope of Cloud Service Providers, initially, to be limited to cloud service providers of Infrastructure as a Service (IaaS) and Platform as a Service (PaaS) who are providing services in India.
- iv. Telecom Service Providers not to be allowed to share infrastructure and platforms related to Telegraph with a Cloud Service Provider (CSP) who is not a member of CSPs' industry body registered with DoT.
- v. The industry body so created to review its experience and further deliberate upon the need to form multiple bodies for different purposes, such as to address requirements of different market segments. DoT may require this review after two years of commencement of the functioning of the first industry body, or such time as it considers appropriate. ■

के रूप में अपने कामकाज को संभालने के लिए पदाधिकारियों का चुनाव।

- ii. उद्योग निकाय को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया जाना है और डॉट द्वारा एम2एम बॉडी के गठन के लिए निर्धारित तरीकों का इस्तेमाल किया जायेगा।
- iii. शुरू में क्लाउड सेवा प्रदायकों का स्कोप, आधारभूत ढांचा के क्लाउड सेवा प्रदाताओं के सेवा (IaaS) और प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा (PaaS) के रूप में सीमित करना है जो कि भारत में सेवायें प्रदान कर रहे हैं।
- iv. दूरसंचार सेवा प्रदायकों को टेलीग्राफ से संबंधित आधारभूत संरचना और प्लेटफॉर्म को क्लाउड सेवा प्रदायकों (सीएसपी) के साथ साझा करने की अनुमति नहीं होगी जो डॉट के साथ पंजीकृत सीएसपी के उद्योग निकाय के सदस्य नहीं हैं।
- v. उद्योग निकाय ने अपने अनुभव की समीक्षा करने के लिए और अलग-अलग उद्देश्यों के लिए कई निकाय बनाने की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श किया, जैसे कि विभिन्न बाजार क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना। पहले उद्योग निकाय के कामकाज शुरू होने के दो साल बाद डॉट को इस समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है या ऐसे समय में जब वह उचित समझे। ■

SCAT DIARY

Here's a listing of some of the major events connected with our industry.

This year your favourite show goes digital

let's e-meet before we re-meet

ABIS
ASIA'S BROADCASTING
& INFOTAINMENT SHOW

2020
'We Go
Digital'
Edition

29 - 31 October 2020
www.abis-digital.com

Organised by
NÜRNBERG MESSE

BI2020
BROADCAST INDIA SHOW

Mob. : +91-99458 26427 /
+91-99458 26440
Email : varun.gaba@nm-india.com /
pranali.raut@nm-india.com
bis@nm-india.com
URL : www.broadcastindiashow.com

SCAT2020
SCAT INDIA TRADESHOW

Mob. : +91-99458 26427 /
+91-70218 50198
Email : varun.gaba@nm-india.com /
scat.sales@nm-india.com
URL : www.scatindiashow.com

CONTX2020
CONTENT INDIA SHOW

Mob. : +91 98110 65185
Email : cis@nm-india.com

URL : www.contentindiashow.com

VISITOR REGISTRATION @ www.scatindiashow.com/visitorregistrationform.aspx